29 मई2015

पाकिस्तान में बलूचिस्तान केलापता लोग

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी|

प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन महमूद की हत्या ने पाकिस्तानी सरकार के लिए एक अजीब कठिन परिस्थितिउत्पन्न की है।बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर एक संगोष्ठी आयोजित करने के बाद बाइक पर सवार हथियारबंद बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी।उन्होंने जलील रेकी नाम के एक लापता बलूची व्यक्ति के पिता, मामा कदीर; ज़ेकर मजीद नामक लापता बलूची की बहन, फरजाना मजीदऔर कई हज़ार अन्य लोगों के साथ काम किया, जो लापता बलूचियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दुख की बात है कि पाकिस्तानी सरकारइसे स्वीकार नहीं करती; यह लड़ाई खत्म होने की आशा नहीं है।

बलूच पहचान का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे पाकिस्तानी राजनीति पर आरोपित किया गया हो, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के समय से ही वह इसमें उलझा हुआ है और समय-समय पर यह हिंसक हो जाता है।इसने विभिन्न आकार और रूपलिए हैं और चाहे पाकिस्तान सैन्य शासक के अधीन हो या वहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो, इसे राज्य द्वारा दबा दिया गया है।बलूच प्रतिरोध को ऐसे आंदोलनों और सक्रियता में आवाज मिली, जो इस समय पांचवें चरण में है और मजबूत आदिवासी विभाजन, बलूच-पश्तून विभाजन, पंजाबी हितों और आर्थिक उत्पीड़न द्वारा हाशिए पर कर दिए जाने के मुद्दों से रेखांकित है।[1]

इस वर्ष की शुरुआत सूबे में एक सामूहिक कब्र की खोज के साथ हुई थी, जिसमेदफनाई गई लाशेंइतनी विकृत हो चुकी थीं कि उन्हें पहचानना संभव नहीं था।[2] ऐसे शव मिलना आम बात हो गई है क्योंकि पूरे प्रांत से लोग गायब होते रहते हैं।बलूचिस्तान निरंतर संघर्षों की एक समाप्त न होने वाली कथा का प्रतिनिधित्व करता है।लंबे समय से चली आ रही नाराजगी, पाकिस्तान के साथ इसके विलय के समय से चली आ रही है, जिससे प्रांत में मौजूदा संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले संघर्षों और वर्तमान संकट को जन्म देने वाले मुद्दे और शिकायतें, प्रांत के लोगों के आर्थिक, जातीय और राजनीतिक अधिकारों की मांगों और आकांक्षाओं से संबंधित हैं।[3]

एक वरिष्ठ बलूच अधिकार कार्यकर्ता, मोहम्मद अली तालपुर के अनुसार, प्रमुख वास्तुकार, नवाब अकबर खान बुगती की मृत्यु के बाद, जो मीर बलाच मारी के साथ क्षेत्र में शांति स्थापित करने वाले प्रमुख वास्तुकार थे, अगस्त 2006 में, बलूच पहचान की रक्षा करने और आक्रामकता का विरोध करने के लिए प्रतिरोध समूह बने। इनमें बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए); डॉ. अल्लाह नज़र की बलूच लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) और बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) शामिल थी। तीनों संगठनों के बीच सहयोग था, जिसने पाकिस्तानी राज्य के लिए काफी परेशानी उत्पन्न की, लेकिन बीएलए के प्रमुख बाला मारी की मृत्यु के बाद, तीनों संगठनों के बीच सहयोग समाप्त हो गया।[4]

तालपुर ने उल्लेख किया है कि पाकिस्तानी सरकार ने बढ़ते बलूच विद्रोह से निपटने के लिए एक चार सूत्री दृष्टिकोण अपनाया।उन्होंने वास्तविक या संदिग्ध बलूच कार्यकर्ताओं को 'भौतिक रूप से समाप्त' करने के लिए गुप्त बल अपनाया, जिससे बलूचों के खिलाफ 'गंदे युद्ध' की शुरुआत हुई।दूसरे, उन्होंने नए नेताओं और नई भर्तियों के कारण पहले से ही अस्थिर, मौजूदा गुटों के भीतर दरारेंडालनी शुरू कर दी।सरकार ने बलूच राष्ट्रवादियों का मुकाबला करने के लिए शफीक मेंगल जैसे मौत के दस्तों का गठन और वित्त पोषण शुरू किया। और अंत में, उन्होंने पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बलूच समाज के सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने को बदलने के लिए मदरसों (इस्लामिक सेमिनारों) को प्रायोजित करना शुरू कर दिया।[5]धन और क्रूर बल की आमद के साथ, बालूची राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों के बीच सामंजस्य बना रहा।गलत सूचना फैलाने के माध्यम से भ्रम और असंतोष पैदा करने के लिए प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया।[6]

इस अवधि के दौरान, सरकार ने अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं और गायब होने वाले लोगों के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया।कराची विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान मामा कादिर ने स्पष्ट रूप से कहा कि “हमारा समर्थन करने के लिए भारत को पहले से कहीं ज्यादा दोषी ठहराया जा रहा है।लेकिन उनके आरोपों को सही प्रमाणित करने वालेसाक्ष्य कहां है?”[7]

पाकिस्तानी सेना ने भारतीय खुफिया एजेंसी को "पाकिस्तान में आतंकवाद भड़काने" के लिए जिम्मेदार ठहराया है।[8] रॉ का नाम लिए बिना, रहेल शरीफ ने "विदेशी सरकारों और खुफिया एजेंसियों" को बलूचिस्तान के विद्रोह में शामिल न होने की चेतावनी दी।[9] पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ‘बलूचिस्तान के अलावा, एफएटीएऔर कराची में भी रॉ के पदचिन्ह पाए गए हैं। हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुछ अपराधियों के इकबालिया बयान रॉ की बढ़ती गतिविधियों का संकेत देते हैं'।[10] पकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारतीय मीडिया के साथ-साथ भारतीय विदेश सचिव को भी मार्च 2015 में बलूचिस्तान और एफएटीएमें भारतीय भागीदारी के बारे में जानकारी दी थी।लेकिन ऐसे सभी आरोपों और शिकायतों काकोई आधार या न्यायोचित सबूत न होने पर भी, पाकिस्तान, भारत को सभी दोष, दुर्भावना और कमजोर शासन के लिए दोषी ठहरा रहा है और आरोप लगा रहा है जिनका उसे अपनी उत्पत्ति से ही सामना करना पड़ा है।

‘लापता पाकिस्तानियों’के मुद्दे को नहीं भूलना चाहिए, जिस पर जस्टिस इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी. राष्ट्रपति मुशर्रफ से भिड़ गए, जिससे मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया; और बाद में उन्हेंफिर से बहाल किया गया और मुशर्रफ को इस्तीफादेना पड़ा। यदि स्थिति को नियंत्रण में नहीं रखा गयातो नागरिक के साथ-साथ सैन्य अधिकारियों को भी नागरिक समाज के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।जो लोग लापता बलूचियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनसे संबंधित बहुत से लोगों के गायब होने का यही कारण हो सकता है।सेमिनार और सम्मेलन रद्द किए जा रहे हैं; छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण सभाओं और विरोध प्रदर्शनों को कानून और व्यवस्था के रखरखाव और चिंताओं के कारण144 सीआरपीसी और इस तरह की गतिविधियों के द्वारा प्रतिबंधित और रद्द किया जा रहा है।[11]

हाल ही में, बलूच मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलूच द्वारा दिए गए एक बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार लापता व्यक्तियों का पता लगाने में विफल रही है, जिससे प्रांत और उसके बाहर बहुत हंगामा हुआ है।[12]हालाँकि, पाँचवें बलूच विद्रोह को शुरू हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन संघीय सरकार और विद्रोहियों के बीच गलतफहमी और संदेह से कोई कमी नहीं आई है और बलूच सरकार उन मुद्दों को संबोधित करने में बुरी तरह से विफल रही है, जिससे आम जनता नाराज थी।उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में ग्वादर में जो भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं या किए जाएंगे, उन्हें सार्वजनिक रूप से स्थानीय आबादी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तभी, ऐसे सभी विकासात्मक कार्यों के दीर्घकालिक लाभ होंगे।[13]विद्रोह आदिवासी बस्तियों के भीतर ही सीमित नहीं है, बल्कि यहसोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर संवाद करने और विश्वविद्यालय परिसरों में दिखाई देने वाले मध्य वर्ग, गैर-पारंपरिक बलूच क्षेत्रों में भी स्थानांतरित हो गया है।

ग्वादर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अक्सर विकृत शव मिलते हैं, जो कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त न्यायिक रूप से गायब करने और हत्याओं के माध्यम से व्यवस्थित सफाई और दमन से संबंधित दावों को मजबूत करते हैं।[14]क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा निर्णयों को पारस्परिक रूप से नागरिक नेतृत्व वाली संघीय सरकार और सेना के नेतृत्व वाले सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा जिस तरह साझा किया जाता है, उसमें प्रांतीय सरकार के लिए व्यावहारिक रूप से कोई भूमिका नहीं होती जिससे उन मुद्दों को संबोधित किया जा सके जो समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण दरार और टकरावउत्पन्न कर रहे हैं।चूंकि प्रस्तावित आर्थिक व्यापार मार्गों और ग्वादर बंदरगाह के विकास ने स्वदेशी आबादी को, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, इसलिए उनमें गंभीर असंतोष है।उन्हें लगता है कि आगामी आर्थिक गलियारे के साथ-साथ परियोजनाओं के लाभों से सूबे की जरूरतों और आवश्यकताओं को अलग कर दिया गया है, जिससे वे विकास परियोजनाओं को अपने आर्थिक हितों और सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के असद उमर ने संघीय सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा, जिसका वे जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने कहा, "एक तरफ, आप दावा करते हैं कि सीपीईसी एक राष्ट्रीय परियोजना है, लेकिन आपने कभी भी प्रांतीय सरकारों, विशेष रूप से पीटीआई-शासित केपी को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि निजी कंपनियों के प्रमुख पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।”[15]

सरकार को उन मुद्दों को पहचानना है जो बलूचियों और राज्य में संघर्ष के मूल में हैं।कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम करने वाले, उपद्रवी, आतंकवादी या अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संगठनों के एजेंट कहने की बजाय, उन्हें एक संयुक्त वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ऐसी किसी भी प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधि के दायरे में लाया जा सके, जो सरकार ने प्रांत के लिए सोचा है।सरकार को जबरन अपहरण और गायब करने की नीति को भी पूरी तरह से छोड़ना होगा, जो एक दशक से अधिक समय से चल रही है।[16]पाकिस्तानी सरकार को उन लोगों को न्याय के अंतर्गत लाने के लिए वास्तविक और आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है, जो बलूच कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना और मारना जारी रखते हैं, और इसे आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय वाचाओं का पालन और पुष्टि करनी चाहिए।[17]

सरकार को बलूच राष्ट्रीय प्रश्न के बारे में भी बातचीत शुरू करनी चाहिए, भले ही वह कोई तात्कालिक निर्णय न ले, क्योंकि बातचीत ही एकमात्र अवसर है, जिसके माध्यम से दोनों पक्षों के बीच विश्वास बनाया जा सकता है।सभी को दोषी ठहराने के रास्ते पर चलने की बजाय, सरकार को बलूचिस्तान प्रांत की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकिईमानदारी से सभी के लिए एक समान विकास पैकेज बनाने का प्रयास किया जा सके; निर्धारित विकास परियोजनाओं में प्रांत के लोगों को पक्षबनायाजाए, और उन्हें अपनी शिकायतों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

****

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।

पादटिप्पणियां:

1 मिक्की कुपेकज, "Pakistan's Baloch Insurgency: History, Conflict Drivers, and Regional Implications", *International Affairs Review*, खंड XX, संख्या 3, स्प्रिंग 2012, p. 96.

2 शेहज़ाद बलोच, "As Operation Begins, Hazaras Bury Blast Victims", *The Express Tribune* January 25, 2014, http://tribune.com.pk/story/663148/as-operation-begins-hazaras-bury-blast-victims/.

3 "Balochistan: Problems and Solutions", Vion21: Global Vision-Local Action, http://www.portmir.org.uk/assets/pdfs/balochistan--problems--solutions.pdf.

4 मीर मोहम्मद अली तालपुर, "Is This the End?",जनवरी 04, 2015, *डेली टाइम्स*, पाकिस्तान, http://www.dailytimes.com.pk/opinion/04-Jan-2015/is-this-the-end.

5 पूर्वोक्त.

6 पूर्वोक्त.

7 मलीहा हामिद सिद्दीकी, "Seminar on Balochistan missing persons held at KU despite curbs and fears", *डाऊन*, मई 7, 2015, http://www.dawn.com/news/1180406.

8 बकीर सज्जाद सईद, "RAW Instigating Terrorism, Says Army", *डाऊन*, मई 8, 2015, http://www.dawn.com/news/1180243.

9 पूर्वोक्त.

10 पूर्वोक्त.

11 "No Sit-ins at Teen Talwar", *डेली टाइम्स*, मई 11, 2015, http://www.dailytimes.com.pk/sindh/08-May-2015/no-sit-ins-at-teen-talwar.

12 "Missing Persons", Editorial, *डाऊन*, मई 11, 2015, http://epaper.dawn.com/DetailNews.php?StoryText=11_05_2015_008_004; Peerzada Salman, "Balochistan CM Concedes Failure in Tracing 'Missing' Persons", *डाऊन*, मई 10, 2015, http://epaper.dawn.com/DetailNews.php?StoryText=10_05_2015_005_006.

13 Peerzada Salman, "Balochistan CM Concedes Failure in Tracing 'Missing' Persons", *डाऊन*, मई 10, 2015, http://epaper.dawn.com/DetailNews.php?StoryText=10_05_2015_005_006.

14 “Mutilated Body Found”, *डाऊन,* मई 9, 2015, http://epaper.dawn.com/DetailNews.php?StoryText=09_05_2015_005_006.

15 खवार घुम्मन, “Special Committee to Oversee CPEC Project”, *डाऊन,* मई 14, 2015, http://www.dawn.com/news/1181864/special-committee-to-oversee-cpec-project

16 मलिक सिराज अकबर, “Pakistani Army Involved in Baloch Kidnappings”, *Deutsche Welle* (DW), December 6, 2013, http://www.dw.de/pakistani-army-involved-in-baloch-kidnappings/a-17275503.

17 “What Future for Balochistan?Global and Regional Challenges”, UNPO Report, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), February 2013, Hague, p. 23, http://unpo.org/downloads/773.pdf.